भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2516
दिनांक 10 अगस्त 2026

प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना

2516 **श्री संजय सेठः**

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के तहत देश भर में वितरित किए गए निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शनों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) ओपन एकरेज लाइसेंसिंग के तहत घरेलू कच्चे तेल अन्वेषण को बढ़ाने के लिए कौन-कौन से कार्यनीतिक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण के लक्षित प्रतिशत को हासिल कर लिया है;

(घ) पाइप्ड प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने वाले शहरी गैस वितरण नेटवर्क के विस्तार से संबंधित आंकड़े क्या हैं; और

(ङ) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में उतार-चढ़ाव से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए कौन-कौन से वित्तीय उपाय किए गए हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क): प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) मई, 2016 में इस उद्देश्य के साथ प्रारंभ की गई थी कि देशभर में गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को बिना जमा राशि के एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया जा सके। दिनांक 01.08.2026 तक, देशभर में लगभग 10.57 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन थे।

(ख): सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने और विदेशी मुद्रा व्यय को घटाने के उद्देश्य से घरेलू कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन को बढ़ावा देने तथा आयात पर निर्भरता कम करने हेतु सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों की भागीदारी के माध्यम से व्यापक नीतिगत, विनियामक और राजकोषीय उपायों की श्रृंखला अपनाई है, जिसमें ऑयलफील्ड्स (नियमन और विकास) संशोधन अधिनियम के माध्यम से विधायी परिवर्तन, देश के अपतटीय क्षेत्रों में 'नो-गो' प्रतिबंधों को हटाना, उत्पादन साझेदारी अनुबंध (पीएससी) से राजस्व साझेदारी अनुबंध (आरएससी) में परिवर्तन, भूकंपीय आंकड़ों के अधिग्रहण और प्रसंस्करण में बड़े पैमाने पर निवेश, अन्वेषणात्मक कुओं की संख्या में वृद्धि आदि जैसे सुधार शामिल हैं ।

(ग): भारत ने चरणबद्ध नीतिगत विकास, हितधारकों के साथ परामर्श, वैज्ञानिक मूल्यांकन और क्षमता निर्माण की दो दशकों से अधिक लंबी प्रक्रिया के बाद 20% एथेनॉल मिश्रण हासिल कर लिया है। इस कार्यान्वयन से पूर्व एथेनॉल उत्पादन क्षमता में क्रमिक वृद्धि, खुदरा अवसंरचना की तैयारी, ईंधन

गुणवत्ता मानकों का निर्धारण तथा वाहन संगतता का आकलन किया गया, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि परिवर्तन क्रमिक, सुरक्षित और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित रहे। एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2025-26 के दौरान, दिनांक 30.06.2026 तक, 743 करोड़ लीटर से अधिक एथेनॉल का मिश्रण किया गया है, जिससे पेट्रोल में औसतन 20% एथेनॉल मिश्रण बनाए रखा गया।

(घ): पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन उपलब्ध कराना सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नेटवर्क के विकास का हिस्सा है, जिसमें पाइपलाइन अवसंरचना और अन्य सुविधाओं का निर्माण शामिल है ताकि घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक इकाइयों को पीएनजी की आपूर्ति की जा सके। यह कार्य पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा अधिकृत संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। 12/12ए सीजीडी बोली प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद, पीएनजीआरबी ने देश के पूरे मुख्य भू-भाग को कवर करते हुए 309 भौगोलिक क्षेत्रों (जीएज़) में सीजीडी नेटवर्क के विकास हेतु संस्थाओं को अधिकृत किया है। दिनांक 31.05.2026 तक, अधिकृत सीजीडी संस्थाओं ने देशभर में 1,70,69,775 पीएनजी (घरेलू) कनेक्शन प्रदान किए हैं, जबकि न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्लयूपी) लक्ष्य के अनुसार 12,65,41,862 पीएनजी (घरेलू) कनेक्शन वर्ष 2034 तक प्राप्त किए जाने हैं।

(ङ): देश में पेट्रोल और डीज़ल के मूल्य बाज़ार द्वारा निर्धारित होते हैं तथा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियाँ (ओएमसीज़) पेट्रोल और डीज़ल के मूल्य निर्धारण पर उपयुक्त निर्णय लेती हैं।

पश्चिम एशिया संकट से पूर्व, कच्चे तेल (भारतीय बास्केट) की कीमत फरवरी 2026 में यूएसडी 69/बैरल थी, जो मार्च 2026 के दौरान बढ़कर यूएसडी 136.68/बैरल हो गई और विभिन्न भू-राजनीतिक एवं बाज़ार कारकों के कारण उतार-चढ़ाव जारी रहा। पेट्रोल और डीज़ल की बिक्री पर भारी नुकसान उठाने के बावजूद, पीएसयू ओएमसीज़ ने इनके मूल्य में केवल मामूली वृद्धि की। वर्तमान में पेट्रोल और डीज़ल का खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) क्रमशः ₹102.12 और ₹95.20 प्रति लीटर है (दिल्ली मूल्य)।

इसके अतिरिक्त, उपभोक्ताओं को इसके प्रभाव से बचाने हेतु, मार्च 2026 में सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल पर उत्पाद शुल्क में ₹10 प्रति लीटर की कमी की, लेकिन साथ ही जिसके परिणामस्वरूप सरकार के कर राजस्व में उल्लेखनीय कमी आई।

घरेलू एलपीजी का खुदरा बिक्री मूल्य जून 2026 से दिल्ली में ₹942 प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर बनाए रखा गया है, जिसमें जून 2026 में प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर ₹700 से अधिक की अप्रत्यक्ष सब्सिडी (अंडर-रिकवरी) और जुलाई 2026 में ₹500 प्रति सिलेंडर की अप्रत्यक्ष सब्सिडी शामिल थी। अगस्त 2026 माह में भी 14.2 किलोग्राम सिलेंडर का खुदरा बिक्री मूल्य ₹188 प्रति सिलेंडर की अप्रत्यक्ष सब्सिडी वहन करता है। 10.5 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) उपभोक्ताओं के लिए लक्षित सब्सिडी ₹300 प्रति सिलेंडर (प्रति वर्ष अधिकतम 4 रिफिल तक) के बाद प्रभावी मूल्य केवल ₹642 प्रति सिलेंडर है।

सरकार यह सुनिश्चित करती रही है कि देश के घरों में घरेलू एलपीजी किफ़ायती मूल्य पर उपलब्ध हो सके, जिसके लिए सरकार ने तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज़) को वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹22,000 करोड़ का मुआवज़ा दिया है तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 में ₹30,000 करोड़ का भुगतान कर रही है। इस मुआवज़े के भुगतान के बाद भी, 31 जुलाई 2026 तक पीएसयू ओएमसीज़ की घरेलू एलपीजी पर संचित अंडर-रिकवरी ₹59,000 करोड़ से अधिक रही।

*****